खास-खबरें

प्रो. खेमसिंह डहेरिया होंगे हिन्दी विवि भोपाल के नए कुलपति

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति पद पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक में हिन्दी विभाग में प्रोफेसर खेमसिंह डहेरिया को नियुक्त किया है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 की धारा-29 की उपधारा एक के तहत कुलपति की नियुक्ति की है। कुलपति के रुप में प्रोफेसर खेमसिंह डहेरिया का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो, के लिए रहेगा।

मुख्यमंत्री ने रोपा हर्र का पौधा

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रवास के दौरान बोरी रिसोर्ट परिसर में हर्र का पौधा रोपा। मुख्यमंत्री प्रतिदिन पौधा रोपण करने की घोषणा के बाद से नियमित रूप से प्रतिदिन पौधा रोपित कर रहे है। इसी अनुक्रम में उन्होंने आज होशंगाबाद संभाग में अपने प्रवास के दौरान पौधा रोपित किया।

चौहान ने पूर्व अपर संचालक जनसंपर्क रवीन्द्र पण्ड्या को दी श्रद्धांजलि

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सेवा निवृत्त अपर संचालक जनसंपर्क रवीन्द्र पण्ड्या के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए अपनी श्रद्धाजंलि अर्पित की। श्री चौहान ने कहा कि अपने लम्बे सेवाकाल में श्री पण्ड्या ने जनसंपर्क एवं अन्य विभागों में विभिन्न पदों पर अपनी सेवायें दी। वे पूर्व में मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रेस अधिकारी के रूप में पदस्थ रहे। श्री पण्ड्या कलम के धनी एवं जनसंपर्क अधिकारी के रूप में एक मिलनसार एवं लोकप्रिय व्यक्ति थे। जनसंपर्क अधिकारी के रूप में उनकी सेवाओं को हमेंशा याद किया जाएगा। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। वे लगभग 73 वर्ष के थे। उन्होंने सुंदरलाल पटवा ,सुश्री उमा भारती , बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान कुल चार मुख्यमंत्रियों के प्रेस अधिकारी के रूप में सेवाएं दीं। उनकी अंत्येष्टि का समय अभी तय नहीं हुआ है। उनके बेटे राजीव पंड्या की अमेरिका से भोपाल आने की प्रतीक्षा की जा रही है। श्री पंड्या वर्तमान में इंडस टाउन भोपाल में निवास कर रहे थे। श्री पंड्या सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया। उन्हें तत्काल बंसल अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों की कोशिश के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका।

डॉ. शाह ने दी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुभकामनाएँ

भोपाल। वन मंत्री डॉ. विजय शाह ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर सभी वन कर्मियों, बाघों और प्रदेश के जंगलों से प्रेम और रूचि रखने वालों को शुभकामनाएँ दी हैं। डॉ. शाह ने अपने संदेश में सभी नगारिकों से वन्य-प्राणियों के संरक्षण और संवर्धन में वन विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सक्रिय भूमिका के निर्वहन का आव्हान किया है। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि आगामी महीनों में होने वाले बाघों की गणना में वन विभाग के अमले और वन्य-प्राणी के संरक्षण में मददगार वन्य-प्राणी प्रेमियों के सहयोग से मध्यप्रदेश टाइगर स्टेट श्रेणी में आएगा।

स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष नियुक्त

भोपाल। राज्य शासन ने महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि को मध्यप्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड में उपाध्यक्ष एवं मध्यप्रदेश गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। स्वामी जी द्वारा दिनांक 29 जुलाई 2021 को विधिवत कार्यभार ग्रहण किया जाएगा। पशुपालन एवं डेयरी

आरक्षण पर ओबीसी महासभा का प्रदर्शन

सीएम हाउस के घेराव से पहले पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लगाया मारपीट का आरोप

भोपाल(काप्र)।

आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने बुधवार को राजधानी में प्रदर्शन किया। बुधवार को सीएम हाउस के घेराव से पहले अंबेडकर पार्क के पास महासभा के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो गई। ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने पुलिस पर महिलाओं समेत कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया।

वहीं, भोपाल डीआईजी इरशाद वली ने कार्यकर्ताओं पर पुलिस से अभद्रता और मारपीट की कोशिश करने की बात कही। ओबीसी महासभा के करीब 100 से ज्यादा कार्यकर्ता गुर्जर भवन के पास आरक्षण की मांगों को लेकर प्रदर्शन के लिए जुटे। दोपहर में कार्यकर्ता ष्टरूहाउस घेराव करने निकले। पुलिस ने इन्हें अंबेडकर पार्क के पास रोक लिया। यहां सीएम हाउस जाने की जिद पर अड़े कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प और धक्का-मुक्की हो गई। पुलिस ने इन्हें हटाया। इसमें महिला कार्यकर्ता भी शामिल थीं। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया। इसके बाद

कार्यकर्ताओं को लेकर जाने वाले वाहन के सामने अन्य कार्यकर्ता लेट गए। इन पर पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग कर हटाया। वहीं, ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय सचिव दिनेश कुमार ने कहा कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे कई कार्यकर्ता घायल हो गए। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस जबरदस्ती गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर लेकर गई है। मामले में भोपाल डीआईजी इरशाद वली ने कहा कि आंदोलनकारियों ने खुद से गिरफ्तारी दी है। पुलिस के साथ अभद्रता और मारपीट की कोशिश भी की गई। वली ने कहा कि शहर में लागू धारा 144 के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार पूरी ताकत के साथ ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण रखने का पक्ष रखेगी। ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण के भाजपा समर्थन में है।

आंदोलन को पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल सहित पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का मिला साथ

मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सियासत गर्मा हो गई है। ओबीसी महासभा के प्रदर्शन को अन्य संगठनों के साथ कांग्रेसद का भी साथ मिला हुआ है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल भी ओबीसी महासभा के प्रदर्शन में शामिल हुए। आंदोलन में शामिल हुए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल की पुलिस जवानों से तीखी बहस हुई। इसके बाद पुलिस ने कई आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी ओबीसी महासभा के समर्थन में उतर आए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हमारी सरकार ने ओबीसी वर्ग के हित के लिये उनके आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था। शिवराज सरकार में इच्छाशक्ति के अभाव, कमजोर पैरवी व ठीक ढंग से पक्ष नही रखने के कारण यह आज तक लागू नहीं हो पाया है? कांग्रेस ओबीसी महासभा के आंदोलन का पूर्ण समर्थन करती है। कमलनाथ ने लिखा कि माँग को लेकर ओबीसी वर्ग के आंदोलन में शामिल लोगों पर हुए बल प्रयोग,दमन व गिरफ़्तारी की कड़ी निंदा करता हूँ। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ओबीसी महासभा के आंदोलन के लिए शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।पटवारी ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार नहीं चाहती कि ओबीसी समाज को आरक्षण मिले। इसमें शिवराज सरकार दोषी है।इसके बाद बीजेपी से मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने मामले में कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि 27 प्रतिश आरक्षण मिले। यह सिर्फ कांग्रेस का राजनीतिक पैंतरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा ओबीसी के खिलाफ़ रही है।ओबीसी को सरकार ने संवैधानिक दर्जा देने का फैसला लिया है। आरक्षण को लेकर स्टैंडिंग कमेटी बनाकर आने वाले समय मे हाई कोर्ट में पक्ष रखा जाएगा।

टीकमगढ़ और दतिया के कांस्य धातु बर्तन पर विशेष आवरण जारी

भोपाल (काप्र)। मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ एवं दतिया में कांस्य धातु शिल्प को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक उपदर्शन के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है । आज भारतीय डाक विभाग, मध्यप्रदेश डाक परिमंडल ने स्थानीय डाक भवन, भोपाल में आयोजित समारोह में मध्यप्रदेश हस्तशिल्प को बढ़ावा देने एवं स्मरणीय बनाने के उदेश्य से टीकमगढ़ और दतिया के कांस्य धातु बर्तन पर विशेष आवरण जितेंद्र गुप्ता, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, मध्यप्रदेश परिमंडल द्वारा जारी किया गया । इस अवसर पर वी. सी. रॉय, पोस्टमास्टर जनरल, जबलपुर परिक्षेत्र, श्री ब्रजेश कुमार, पोस्टमास्टर जनरल, इंदौर परिक्षेत्र, एच. जी. एस. धाकड़, महाप्रबंधक (वित्त), डाक लेखा एवं डॉ. एस. शिवराम, निदेशक डाक सेवाएं (मुख्यालय) उपस्थित रहे । टीकमगढ़ एवं दतिया में कांस्य धातु की ढलाई का कार्य तीन शताब्दियों से भी अधिक समय से किया जा रहा है । इस शिल्प से सुंदर सजावटी समान एवं बर्तन तैयार किए जाते हैं । उक्त विशेष आवरण भोपाल जीपीओ एवं इंदौर जीपीओ के फिलैटली ब्यूरो में डाक टिकट एवं विशेष आवरण संग्रहकर्ताओं हेतु उपलब्ध है ।

आरएनटीयू में फल प्रशिक्षण पुस्तिकाओं का विमोचन

भोपाल। रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और ग्लोबल विकास ट्रस्ट महाराष्ट्र द्वारा तैयार की गई तीन फल प्रशिक्षण पुस्तिकाओं का विमोचन विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में किया गया। विश्वविद्यालय के कृषि संकाय द्वारा तैयार की गई अमरुद प्रशिक्षण, सीताफल प्रशिक्षण व पपीता प्रशिक्षण पुस्तिका के लेखक आरएनटीयू के कृषि संकाय के डीन डॉ. अनिल कुरचानिया और ओम रघुवंशी हैं। यह विमोचन ग्लोबल विकास ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी मयंक गांधी, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. ब्रम्हप्रकाश पेठिया, कुलसचिव डॉ. विजय सिंह और आईक्यूएसी के निदेशक श्री नितिन वत्स के द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने हेतु आरएनटीयू और ग्लोबल विकास ट्रस्ट महाराष्ट्र के मध्य एमओयू किया गया है। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगाए जा रहे इन फल वृक्षों के सुदृढ़ विकास के लिये विश्वविद्यालय से समय-समय पर विशेषज्ञ सलाह किसानों के बगीचों पर प्रत्यक्ष रुप से उपस्थित होकर दी जा रही है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. ब्रम्हप्रकाश ने ग्लोबल विकास ट्रस्ट के संस्थापक श्री मयंक गांधी का स्वागत करते हुए उनके द्वारा किये गये ग्लोबल परली महाराष्ट्र के सफल मॉडल की सराहना की।

15 अगस्त के बाद इंदौर मेट्रो के काम तीव्र गति से शुरू होंगे : सिलावट

मंत्री भूपेंद्र सिंह और तुलसी सिलावट ने भेंट कर मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम जल्दी शुरू करने पर बात की

भोपाल(काप्र)।

जल संसाधन मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भोपाल में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से भेंट कर इंदौर मेट्रो परियोजना के संबंध में चर्चा की। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सभी आवश्यक कामों के टेंडर कर दिए गए हैं और 15 अगस्त के बाद सभी काम शुरू किए जाएंगे।

स्टेशन, अंडरग्राउंड स्टेशन, एलिवेटेड स्टेशन, डिपो, विद्युत लाइन ट्रांसमिशन, और कनेक्टिविटी स्टेशन की ड्राइंग और निर्माण के लिए टेंडर कर अनुबंध किया जा रहा है।

श्री सिलावट ने कहा कि इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट में काम लंबित है। सभी कामों की समय सीमा निर्धारित की जाए। श्री सिंह ने बताया कि गांधीनगर से मुमताज बाग येलो लाइन का काम शुरू होकर दिसंबर 2023 तक पूर्ण किया जाएगा। मुमताज बाग से रेलवे स्टेशन का काम अप्रैल 2024 तक पूरा किया जाने के निर्देश दिए गए हैं इसके

साथ ही गांधीनगर से रेलवे स्टेशन का मेट्रो के काम मई 2025 तक पूर्ण किया जाएगा। श्री सिलावट ने कहा कि इंदौर मेट्रो परियोजना में मेट्रो के प्रथम चरण में 31 किलोमीटर लंबाई की मेट्रो ट्रैक निर्माणाधीन है । जिसमें 24 किलोमीटर से अधिक लंबाई में एलिवेटेड मेट्रो ट्रैक और 7.48 किलोमीटर लंबाई का अंडरग्राउंड रेलवे मेट्रो ट्रैक बनाया जाना है जिसकी लागत 7500 करोड़ की है । जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के 50-50 के अनुपात में वित्तीय भार आना है। लगभग 440 करोड़ के काम पीपीपी मोड पर किए जाना प्रस्तावित है। मेट्रो स्टेशन के लिए 30 स्थानों को चिन्हित किया गया है। प्रथम चरण में येलो लाइन का 31 .54 किलोमीटर लंबाई का मेट्रो ट्रैक बनना है जिसमें गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर ,भोरासला चौराहा, रेडिसन चौराहा, मुमताज बाग कॉलोनी से रेलवे स्टेशन और स्टेशन से गांधीनगर तक मेट्रो ट्रेन का काम तीव्र गति शुरू होगा। गांधीनगर में मेट्रो के डिपो के लिए जगह आरक्षित है जिसका काम भी जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि स्टॉक डिपो के लिए डिजाइन के अनुबंध किए जा चुके हैं विद्युत रिसीविंग और फूड डिसट्रीब्यूशन वितरण के डिजाइन कंसलटेंसी सेवा के लिए 5.99 करोड़ की लागत के अनुबंध हो चुके हैं। मेट्रो के अंडरग्राउंड स्टेशन, टनल्स , डिपो के लिए जिओ टेक्निकल इन्वेस्टिंग स्टडी के लिए भी अनुबंध हो चुके हैं विद्युत लाइन संशोधन और विस्थापन के लिए भी 50 करोड़ की लागत से कार्य किया जा रहा है।

श्री सिंह ने बताया कि इंदौर मेट्रो की येलो लाइन को शीघ्र पूरा करने के लिए तीव्र गति से काम शुरू कराया जा रहा है। 421 करोड़ की लागत से सात एलिवेटेड मेट्रो रेल स्टेशन का डिजाइन निर्माण के लिए फरवरी 20 में ही टेंडर किए जा चुके हैं। इसी प्रकार इंटरफेयर लोकेशन और डिपो कनेक्टिविटी और 9 एलिवेटेड स्टेशन की डिजाइन के लिए 1000 करोड़ की निविदा मार्च में जारी की जा चुकी है। अनुबंध की प्रक्रिया जारी है। 15 अगस्त के बाद सभी कार्य स्थलों पर तीव्र गति से काम शुरू कर दिए जाएंगे।

अवैध शराब के धंधे को आबकारी और पुलिस का संरक्षणः दिग्विजय

भोपाल(काप्र)।

मंदसौर जिले में आबकारी मंत्री के विधानसभा क्षेत्र के खकराई गांव में जहरीली शराब पीने से मौत होने के मामले पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा से इस्तीफा मांगा है।

बुधवार को दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि अवैध शराब का धंधा पुलिस और आबकारी विभाग के संरक्षण में चलता है और करोड़ों की रिश्वत प्रति माह वसूली जाती है। क्या आबकारी मंत्री जी को अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहे अवैध शराब के धंधे की जानकारी नहीं थी? क्या यह संभव है? क्या मंत्री जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए?

इससे पहले एक अन्य ट्वीट में दिग्वियज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में अवैध शराब का बहुत बड़े पैमाने पर धंधा चला हुआ है। जनवरी 2021 में नूराबाद थाना मुरैना में 26 लोगों की जान गई। अब स्वयं भाजपा सरकार के आबकारी मंत्री के मल्हारगढ़ निर्वाचन क्षेत्र पीपल्या मंडी थाना क्षेत्र जिला मंदसौर में 11 लोगों की मौत का समाचार है। इस मामले में कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मामले में सरकार को घरते हुए जहरीली शराब पीने से मौत के आंकड़े बढ़ने और आंकड़ों को छिपाने के आरोप लगाए थे। साथ ही उन्होंने सीएम पर कटाक्ष किया था कि पता नहीं माफियाओं को गाड़ने, टांगने की बात कहने वाले शराब माफियाओं और दोषियों को बचाने में क्यों लगे हैं? प्रदेश सरकार ने रविवार को 6 लोगों की जहरीली शराब से मौत की जांच के लिए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की है। वहीं, आबकारी निरीक्षक, थाना प्रभारी और बीट प्रभारी को सस्पेंड कर दिया।

खास खबर | कई नवाचारों की बदौलत मिला यह मुकाम...

मप्र के पास है टाइगर स्टेट का गौरवशाली और जवाबदारी भरा ताज

भोपाल(काप्र)।

अखिल भारतीय स्तर पर तीन साल पहले हुई बाघ गणना में 526 बाघों के साथ पहले स्थान पर काबिज रहकर मध्यप्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। इस साल होने वाली गणना के प्रारम्भिक संकेतों के अनुसार इस बार भी मध्यप्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में मान्यता मिलने की प्रबल संभावना है।

वर्ष 2010 और 2014 की गणना में कर्नाटक स्टेट के सर्वाधिक बाघों की संख्या के साथ पहले स्थान पर रहने को छोड़ दें तो मध्यप्रदेश के पास ही पिछले दशक में टाइगर स्टेट का दर्जा रहा है।

प्रदेश सरकार ने वन्य-प्राणी संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कई नवाचारों को लागू किया, जिनकी बदौलत मध्यप्रदेश टाइगर स्टेट की प्रक्रिया का आधार स्तंभ बना। पिछले डेढ़ दशक में बाघों और अन्य वन्य-प्राणियों के लिए आवास क्षेत्र की सुविधा कराने के लिए संरक्षित क्षेत्रों से 167 ग्रामों का मुकम्मबल स्थान पर पुनर्स्थापन कराया गया। दुर्गम वन क्षेत्रों के अंतर्गत न्यूनतम सुविधाओं के साथ रह रही 15 हजार से ज्यादा परिवार इकाइयों को वनों से बाहर लाया जाकर ग्राम-नगरों में बसाया गया। नतीजा यह हुआ कि वन्य-प्राणियों को व्यवधान रहित स्वछंद रूप से रहवास मिल गया। साथ ही वनवासियों की माली हालत में भी सुधार हुआ। इन तमाम नवाचारों में राज्य सरकार ने 900 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराई गई।

टाइगर रिजर्व के अलावा मौजूद हैं बाघ: प्रदेश के बाघ न केवल टाइगर रिजर्व में है बल्कि अन्य क्षेत्रीय वन मण्डलों अपितु भोपाल जैसे बढ़े शहरों की सीमा में भी अन्य प्राणी की तरह विचरण करते पाए जाते हैं। वर्ष 2018 में पन्ना से बाघों का अस्तिव ही समाप्त हो गया था। वन विभाग द्वारा बाघ संरक्षण के लिए सक्रिय पहल की गई, जिसमें बाघों को अन्य संरक्षित क्षेत्रों से लाकर पन्ना टाइगर रिजर्व में पुनर्स्थापित किया गया। पिछले 9 वर्ष की सतत प्रक्रिया के कारण आज पन्ना टाइगर रिजर्व पुराने वैभव की ओर लौट चुका है। यहाँ 20 से ज्यादा वयस्क बाघ और 15 अवयस्क बाघ/शावक मौजूद हैं। सम्पूर्ण पन्ना लैंड स्केप में शावकों सहित तकरीबन 50 बाघ उपलब्ध हैं।

तीन चरण में ऐसे होती है बाघों की गणना: भारत में बाघों की गणना हरेक 4 साल में की जाती है। इसके तीन चरण निर्धारित हैं। प्रथम चरण में बाघों, अन्य मांसाहारी तथा बड़े शाकाहारी प्राणियों के चिन्ह अर्थात उनके पंजों के निशान, उनकी विष्ठा, खरोंच के निशान और उनके द्वारा किए गए शिकार आदि के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इस बाघ ऑकलन को फेस वन कहा जाता है। यह प्रक्रिया एक सप्ताह तक चलती है। वन कर्मचारी इन सातों दिन जंगलों में भ्रमण कर वन्य-प्राणियों की उपस्थिति के चिन्ह पहले तीन दिन और अगले तीन दिन वन्य-प्राणियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति की संख्या एकत्रित करते हैं।

द्वितीय चरण में वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशालाओं में बाघ आकलन किया जाता है। वैज्ञानिक सेटेलाईट द्वारा एकत्र किए गए आँकड़ो का अध्ययन कर बाघ के रहवास क्षेत्र की स्थिति के बारे में आँकड़ों जुटाते हैं। तीसरे चरण में कैमरा ट्रेपिंग की जाकर बाघों की उपस्थिति के चित्र लिए जाते हैं। इन तीन चरणों में मिले आँकड़े और सबूतों के सांख्यिकी विश्लेषण से किसी क्षेत्र में बाघों की संख्या का आकलन निकाला जाता है। अखिल भारतीय बाघ गणना में सम्पूर्ण भारत में तकरीबन 30 हजार बीटो में गणना कार्य किया जाता है। इसमें 9 हजार बीट केवल मध्यप्रदेश में ही मौजूद हैं। यह एक बहुत श्रम साध्य और व्यापक कार्य है। प्रदेश के वन विभाग ने इस चुनौती को अंगीकार करते हुए वर्ष 2017 से अपनी तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया। इसके अंतर्गत वन रक्षकों के कई चरण आयोजित कर उन्हें इसके काबिल बनाया गया। इस तरह दक्षतापूर्ण तरीके से दुष्कर कार्य की गणना कराई जाती है।